बाल श्रम पर शैक्षणिक प्रदर्शन और सामाजिक प्रभाव के निहितार्थः उत्तर प्रदेश का एक मामला

IMPLICATIONS OF EDUCATIONAL PERFORMANCE AND SOCIAL IMPACT ON CHILD LABOUR: A CASE STUDY OF UTTAR PRADESH

मन्जीत कुमार यादव[1]
प्रोफेसर (डॉ.) आर. के. एस अरोड़ा[2]
[1]शोधार्थी, शिक्षा विभाग, भगवन्त विश्वविद्यालय, अजमेर, राजस्थान, भारत
[2]शोध निर्देशक, शिक्षा विभाग, भगवन्त विश्वविद्यालय, अजमेर, राजस्थान, भारत

Manjeet Kumar Yadav[1], Professor (Dr.) R. K. S Arora[2]
[1]Researcher, Department of Education, Bhagwant University, Ajmer, Rajasthan, India
[2]Research Director, Department of Education, Bhagwant University, Ajmer, Rajasthan, India

सारांश

यह लेख उत्तर प्रदेश में शिक्षा हितधारकों द्वारा बाल श्रम नीति को लागू करने में बाधा की रिपोर्ट करता है। माना जाता है कि बाल श्रम का असर बच्चे के शारीरिक, सामाजिक और बौद्धिक विकास पर पड़ता है। बाल श्रम कानून और नीतियां बनाकर बाल श्रम से निपटने के सरकारी प्रयासों के बावजूद, उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में बाल श्रम की दर अभी भी प्रचलित है। माता–पिता को अपने बच्चों के लिए शिक्षा के मूल्य के बारे में जागरूक होना चाहिए। सरकार को गरीबी से लड़ने के तरीके खोजने चाहिए और बाल श्रम को खत्म करने के लिए सभी हितधारकों को हाथ मिलाना चाहिए।

मुख्य शब्दः बाल श्रम, कानून और नीतियां, सामाजिक–आर्थिक प्रभाव, कार्यान्वयन

परिचय

बचपन मानव जीवन की सबसे मासूम अवस्था है। यह जीवन का वह चरण है जहां बच्चा प्यार करने, खेलने और नई चीजें सीखने के लिए सभी तनावों से मुक्त होता है और यह परिवार के सदस्यों का प्रिय होता है। लेकिन ये कहानी का सिर्फ एक पहलू है। दूसरा पक्ष तनाव और

बोझ से भरा है. यहां मासूम बच्चा परिवार की कमाई की मशीन है, जो परिवार की जरूरतों और इच्छाओं को पूरा करने के लिए पूरे दिन काम करता है। यह बाल श्रम है (अन्यागरवाल 2009)।

उत्तर प्रदेश में बाल श्रम व्यापक रूप से फैला हुआ है। सरकारी आंकड़े, घरेलू जनगणना (1999) के अनुसार, 5–7 साल की उम्र के युगांडा के लाखों बच्चे किसी न किसी तरह के काम में शामिल हैं और उन्हें काम के लिए बाहर जाने के लिए स्कूल छोड़ना पड़ सकता है, जबकि कई लोग खुद को हथियारों से लैस कर रहे हैं। एक सहायता एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय बचाव समिति (आईआरसी) और एवीएसआई फाउंडेशन (2006) द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट सर्वेक्षण से पता चला है कि उत्तर प्रदेश में 15% बच्चे पत्थर तोड़ने, जलाऊ लकड़ी इकट्ठा करने और वेश्यावृत्ति जैसे कठोर, खतरनाक श्रम में शामिल हैं। भारत का संविधान (1995) अध्याय 1, अनुच्छेद 34 (4) एक बच्चे को खतरनाक और शोषणकारी काम से सुरक्षा प्रदान करता है। यह अनुमान लगाया गया था कि भारत में 5–17 वर्ष की आयु के 7.9 मिलियन बच्चे बाल श्रमिक के रूप में काम कर रहे थे। केवल 3 में से 1 बच्चा, जिनमें से अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों से हैं।

इस लेख के संदर्भ में, नीति को विशिष्ट उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए जानबूझकर की गई कार्रवाई के कारण के रूप में परिभाषित किया गया है, ओवोलाबी (2005)। अपने सरलतम रूप में, नीति विदेश में दिए गए वक्तव्य को संदर्भित करती है जो भविष्य के लक्ष्यों और आकांक्षाओं को दर्शाता है और उन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए दिशानिर्देश प्रदान करता है। सरकार ने बच्चों को खतरनाक काम से बचाने के लिए बाल श्रम कानून का गठन किया जो अन्यथा उनके शारीरिक और मानसिक विकास में बाधा उत्पन्न कर सकता था। हालाँकि, बाल श्रम नीति के कार्यान्वयन ने कुछ शिक्षाविदों की रुचि को आकर्षित किया है। शैक्षणिक प्रदर्शन बच्चे की शिक्षा पर प्रतिबिंबित होने वाला संपूर्ण प्रदर्शन है। मीर्स, (1987) ने कहा कि शिक्षा प्रदर्शन स्कूल के माहौल में एक बच्चे या युवा की कुल भागीदारी को दर्शाता है जिसमें सामाजिक और भावनात्मक विकास, संचार और कक्षाओं के साथ–साथ कक्षा के बाहर की गतिविधियों में भागीदारी शामिल है। खराब प्रदर्शन का मतलब है कि एक बच्चा आवश्यक मानकों के अनुरूप नहीं है, यानी देर से आना, पाठ से बचना, परीक्षा में खराब उपलब्धि। जब विद्यार्थियों के शैक्षणिक प्रदर्शन को देखा गया, तो इसने विद्यार्थियों के बीच खराब प्रदर्शन के औचित्य का संकेत दिया। इसे देर से आने, अनुपस्थिति, परीक्षा परिणाम के संदर्भ में देखा गया। भारत से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, विशेष रूप से बनारस जिले में, 2005 से 2010 तक प्राइमरी लीविंग परीक्षा में बैठने वाले 2307 विद्यार्थियों में से केवल 21 विद्यार्थी डिवीजन 1 में उत्तीर्ण हुए, 176 डिवीजन 2 में और 278 डिवीजन यू में असफल रहे। बाल श्रम से निपटने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे तमाम प्रयासों के बावजूद, स्कूल जाने वाले बच्चों को सड़क किनारे या तो खाद्य पदार्थ बेचते या घूमते देखा जा रहा है। बनारस जिले में बाल श्रम बड़े पैमाने पर

हुआ है, खासकर एलआरए युद्ध के कारण हुए उत्तरी विद्रोह के बाद। जीवन–यापन कठिन हो गया, विद्यार्थियों की शिक्षा बाधित हो गईय अधिकांश बच्चों ने पानी लाने और सड़क के किनारे छोटी–छोटी चीजें बेचने जैसे सस्ते श्रम का सहारा लिया। लोग नील नदी में मछली पकड़ने पर निर्भर हैं। हालाँकि, अत्यधिक मछली पकड़ने और छोटे आकार के मछली पकड़ने वाले जालों के इस्तेमाल के कारण नदी में मछलियों की संख्या काफी कम हो गई है। परिणामस्वरूप, लोगों ने जीवित रहने के लिए अपने बच्चों को छोटे–मोटे व्यवसाय और सस्ते श्रम के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है।

विद्यार्थियों के शैक्षणिक प्रदर्शन पर बाल श्रम का प्रभाव

अब्राका (2010) ने पाया कि 22ः छात्रों का शैक्षणिक प्रदर्शन भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के माध्यमिक विद्यालयों में कक्षाओं में भाग लेने से प्रभावित था। इसलिए उन्होंने पहचाना कि उपस्थिति में वृद्धि से छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन में भी वृद्धि होगी।

बाल श्रम गरीबी का एक पहलू है, उनका संबंध अनुभवजन्य साहित्य में अच्छी तरह से स्थापित है। दुविधा यह है कि क्या यह बाल श्रम आर्थिक दृष्टिकोण से कुशल है और क्या यह स्कूल में बच्चे की उपलब्धि और व्यक्तिगत विकास में बाधक है। बाल श्रम बाजार में सरकारी हस्तक्षेप के लिए पारंपरिक तर्क बाह्यताओं के अस्तित्व पर आधारित है – माता–पिता अपने बच्चों की उच्च शिक्षा प्राप्ति से उत्पन्न होने वाली सकारात्मक बाह्यताओं को पूरी तरह से आत्मसात नहीं करते हैं और इसलिए अपनी संतानों के लिए शिक्षा के संदर्भ में प्रावधान नहीं करते हैं, एनाबेल (2008)।

एलआरए द्वारा कई बच्चों का अपहरण कर लिया गयाय उनमें से कुछ भागने में सफल रहे और वापस आ गए, लेकिन जिस आघात से वे गुजरे, उसके कारण वे अपनी शिक्षा जारी नहीं रख सके। अमेरिकी विदेश विभाग, देश की रिपोर्ट (2006) के अनुसार, अनाथ बच्चे जीवित रहने और अपने भाई–बहनों की देखभाल के लिए काम करने के लिए स्कूल छोड़ देते हैं। उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत के बच्चों का (एलआरए) द्वारा अपहरण कर लिया गया और अन्य क्षेत्रों में उनकी तस्करी की गई। अपहरण किए जाने पर, उन्हें रसोइया, कुली, कृषि श्रमिक, सैनिक और गार्ड बनने के लिए मजबूर किया जाता है। भागने का प्रयास करने वाले अन्य बच्चों की हत्या में भाग लेने के लिए कई लोगों को पीटा गया, बलात्कार किया गया और उनकी मरम्मत की गई।

बाल श्रम को एक गंभीर समस्या माना जाता है, क्योंकि यह बच्चों के बौद्धिक और शारीरिक विकास, विशेषकर छोटे बच्चों के लिए विनाशकारी माना जाता है। खतरा उन बच्चों के लिए और भी बढ़ जाता है जो खतरनाक उद्योगों में काम करते हैं। बाल श्रम जाल के पीछे यही सिद्धांत है। यदि किसी बच्चे को पूरे दिन नियोजित किया जाता है, तो बच्चा अशिक्षित रह

जाता है और परिणामस्वरूप एक वयस्क के रूप में उसकी उत्पादकता कम होती है। इसलिए बाल श्रम सीधे तौर पर विकासशील देशों में वयस्क बेरोजगारी में योगदान दे सकता है। एक प्रमुख चेतावनी यह है कि बाल श्रम के ऐसे दीर्घकालिक गतिशील परिणामों का बहुत कम इलाज है, (एनाबेल 2008)।

बाल श्रम के बारे में माता–पिता की धारणाएँ

वर्नर (2006) बाल श्रम के पक्ष में तर्क देते हैं। उन्होंने कहा कि कई गरीब इलाकों में, बाल श्रम ही परिवार और इकाई के बीच का सब कुछ है और सर्वव्यापी, जीवन के लिए खतरा, गरीबी है। प्रति व्यक्ति आय बढ़ने से बाल श्रम में स्पष्ट रूप से गिरावट आई है। इन रोटी कमाने वालों को खुद को और अपने अनैतिक पाखंड से ऊपर उठने के अवसरों से वंचित करना। सिर्फ इसलिए कि वे कम उम्र के हैं इसका मतलब यह नहीं है कि हमें उन्हें पूरी तरह से अस्वीकार कर देना चाहिए, उन्हें जीवित रहने का अधिकार है। कोई सिर्फ यह नहीं कह सकता कि वे काम नहीं कर सकते, बल्कि विकल्प उपलब्ध कराना चाहिए। बिना कुछ किए बाल श्रम रोकना अधिक चुनौतियाँ पैदा कर सकता है। यदि वे आवश्यकता से बाहर काम कर रहे हैं, जैसा कि उनमें से अधिकांश कर रहे हैं, तो उन्हें रोकना उन्हें वेश्यावृत्ति या बड़े व्यक्तिगत खतरों वाले अन्य रोजगार में मजबूर कर सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे स्कूल में रहें और शिक्षा प्राप्त करें जिससे उन्हें बुनियादी शिक्षा प्राप्त करने और जीवन और अस्तित्व के मुद्दों पर उनकी मानसिकता में सुधार करने में मदद मिलेगी।

ग्रामीण और गरीब समुदाय शायद ही कभी अपने स्कूल जाने योग्य उम्र के दो–तिहाई से अधिक बच्चों को नियमित आधार पर शिक्षा देना पसंद करते हैं। यह विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में सच है जहां बाल श्रम व्यापक रूप से फैला हुआ है। कई कठोर माता–पिता द्वारा विशेष रूप से महिलाओं की शिक्षा को अफोर्डेबल विलासिता माना जाता है। कई संस्कृतियों में बच्चे की नैतिकता और चरित्र की ताकत को आकार देने और उसे व्यापार सिखाने में काम को अभी भी अपरिहार्य माना जाता है, (वेनिन, 2009)।

बाद के वर्षों में स्वयं और परिवार के भरण–पोषण के लिए शिक्षा की बुनियादी आवश्यकता से परे, मुफ्त और सुलभ शिक्षा के शून्य में कई सामाजिक बुराइयाँ दिखाई देती हैं। यूनिसेफ के अनुसार, दुनिया भर के ग्रामीण क्षेत्रों में 100 मिलियन से अधिक बच्चे कृषि कार्य करते हैं, जहां शिक्षा की पहुंच, प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता और शैक्षिक आपूर्ति गंभीर रूप से सीमित है। हालाँकि, गरीबी पहुंच में सबसे बड़ी बाधा बनी हुई है। स्कूल की फीस का भुगतान करना उन कई परिवारों के लिए असंभव है जो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, विशेष रूप से चल रहे खाद्य संकट को देखते हुए और जब उनके परिवारों और

समुदाय में एचआईवीध्एड्स का बोझ हो। यह सुनिश्चित करने के लिए कि बच्चे शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम हैं, पूर्ण स्कूल फीस उन्मूलन आवश्यक है, (वासेमा, 2000)।

बाल श्रम के सामाजिक आर्थिक प्रभाव

भारत में, बच्चों को आम तौर पर छोटे वयस्कों के रूप में माना जाता हैय छोटी उम्र से ही हर बच्चे को घर में झाड़ू लगाने या पानी लाने जैसे काम करने होंगे। बच्चों को दुकानों या सड़कों पर काम करते देखना भी आम है। गरीब परिवार अक्सर अपने बच्चों को एक अमीर रिश्ते में नौकरानी या घरेलू लड़के के रूप में इस उम्मीद में भेजते हैं कि उन्हें शिक्षा मिलेगी, (वक्निन, 2009)।

बेनेट, होडने और शेरे (2010) के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का अनुमान है कि 5–17 वर्ष की आयु के 246 मिलियन बच्चे वर्तमान में ऐसी परिस्थितियों में काम करते हैं जिन्हें अवैध, खतरनाक या अत्यधिक शोषणकारी माना जाता है। कम उम्र के बच्चे दुनिया भर में सभी प्रकार की नौकरियों में काम करते हैं, आमतौर पर क्योंकि वे और उनके परिवार बेहद गरीब होते हैं। बड़ी संख्या में बच्चे व्यावसायिक कृषि, मछली पकड़ने, विनिर्माण, खनन और घरेलू सेवाओं में काम करते हैं। कुछ बच्चे अवैध गतिविधियों जैसे नशीली दवाओं के व्यापार और वेश्यावृत्ति या अन्य दर्दनाक गतिविधियों जैसे सैनिकों की सेवा में काम करते हैं। बाल श्रम में बच्चों की भागीदारी देश के न्यूनतम आयु कानून का उल्लंघन है और उन्हें स्कूल जाने से रोकती है, जिससे श्रम मानक कमजोर होते हैं और बच्चों के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को खतरा होता है। उन्हें गुलामी, बाल तस्करी, ऋण बंधन, जबरन श्रम और अवैध गतिविधियों जैसे श्रम दुर्व्यवहार में शामिल करता है।

बाल श्रम नीति के कार्यान्वयन में बाधा

मवेबेज (2010) ने कहा कि, बाल श्रम की व्यापकता और इससे जुड़े कई खतरों के बावजूद, इस घटना पर हाल ही में शोधकर्ता शिक्षाविदों और नीति निर्माताओं का ध्यान गया है, और तब तक नहीं जब तक कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के अनुमानों में बड़ी और बढ़ती संख्या दिखाई न दे। दुनिया भर में कामकाजी बच्चों की. अब यह माना जाता है कि बाल श्रम से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए, इसके कारणों, भूमिकाओं और निहितार्थों की जानकारीपूर्ण समझ के साथ नीतियां बनाई जानी चाहिए। बाल श्रम अभी भी आम है और भारत में कम उम्र से ही शुरू हो जाता है।

बाल श्रम पर नीति कार्यान्वयन सीधा–सरल नहीं है। उदाहरण के लिए, बाल श्रम पर पूर्ण प्रतिबंध घर के आर्थिक कल्याण और बहुत गरीब क्षेत्रों में एक बड़ी अल्पकालिक लागत होगी काम का विकल्प तीव्र भूख या भुखमरी सहना हो सकता है।

वामाकुयू (2010) ने पाया कि युगांडा में 2.7 मिलियन से अधिक बच्चे बाल श्रम में शामिल हैं, इनमें से 35% काम करते हैं और एक ही समय में कक्षाओं में जाते हैं, 3% प्रतिशत स्कूल गए बिना काम करते हैं, लगभग 4.7% न तो काम में शामिल होते हैं और न ही उपस्थित होते हैं विद्यालय।

बच्चे फसल की खेती और चाय, तम्बाकू और चावल से संबंधित व्यावसायिक कृषि में काम करते हैं। शहरी क्षेत्रों में, बच्चे सड़कों पर छोटी–छोटी वस्तुएँ बेचते हैं, दुकानों में काम करते हैं, या व्यावसायिक सेक्स उद्योगों में शामिल होते हैं। बच्चे घरेलू काम, पत्थर उत्खनन, पत्थर तोड़ने और तस्करी में भी लगे हुए हैं।

यौन शोषण के लिए लड़कियों की तस्करी ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में की जाती है, जिसके परिणामस्वरूप एचआईवी/एड्स संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है, जिससे कई लोग अनाथ हो जाते हैं।

बटानिंगया (2010) ने पाया कि प्राथमिक विद्यालय शुरू करने वाले यूपीई के लगभग 60% छात्र प्राथमिक सातवीं कक्षा (पी7) पूरी करते हैं। हालाँकि, 2002 में पी1 शुरू करने वाले 1,712,420 विद्यार्थियों में से केवल 516,890 विद्यार्थी 2009 में पीएलई में बैठे, जो केवल 30% का प्रतिनिधित्व करता है। मंत्रालय के आँकड़े बताते हैं कि बाकी लोग दोहराते हैं या बाहर हो जाते हैं। इससे यह भी पता चला कि कक्षा के अनुसार विद्यार्थियों का वितरण, P1 25%, P2 25%, P3 16%, P4 14%, P5 13%, P6 10%, और P7 6% है। इसने भारी गिरावट के लिए निम्नलिखित कारणों को जिम्मेदार ठहराया, रुचि की कमी 46% पारिवारिक जिम्मेदारी 15%, बीमारी 12% रोजगार 4%, विवाह 4%, स्कूल फीस 3%, गर्भावस्था 2%, बर्खास्तगी 1% और अन्य 13%।

रोजगार अधिनियम 32(1–3) रोजगार के लिए न्यूनतम आयु 14 वर्ष निर्धारित करता है। 12 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे हल्के काम में संलग्न हो सकते हैं जिससे उनकी शिक्षा में बाधा नहीं आती है और 18 वर्ष और उससे अधिक के वयस्क की देखरेख में होता है। 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी व्यवसाय या कार्यस्थल पर काम करने से प्रतिबंधित किया गया है। कानून कहता है कि शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे के बीच किसी भी बच्चे को खतरनाक काम में नहीं लगाया जाएगा।

युगांडा के संविधान अध्याय 4 में कहा गया है कि 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सामाजिक और आर्थिक शोषण से बचाने का अधिकार है और उन्हें किसी भी खतरनाक काम में नियोजित नहीं किया जाना चाहिए जो अन्यथा उनके स्वास्थ्य, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, नैतिक या सामाजिक विकास को खतरे में डाल देगा। , या ऐसा काम जो उनकी शिक्षा में बाधा उत्पन्न करेगा।

नीति डिजाइन में मुख्य विभाजन कानूनी हस्तक्षेप जैसे बाल श्रम पर प्रतिबंध और सहयोगात्मक हस्तक्षेप के बीच हैय सार्वजनिक कार्रवाई, जो माता–पिता को अपनी मर्जी से बच्चों को श्रम बल से वापस लेने के लिए प्रेरित करने के लिए आर्थिक माहौल प्रदान करती है। इन नीतियों में प्रौद्योगिकी में प्रगति, वयस्कों में सुधार शामिल हो सकते हैंय श्रम बाजार और स्कूली शिक्षा के लिए माल की अधिक उपलब्धता।

ओवोलाबी (2005) ने कहा कि शिक्षा नीति के सफल कार्यान्वयन के लिए राजनीतिक लामबंदी की आवश्यकता होती हैय सहायता। व्यवस्थित प्रयोग और रिकॉर्ड किए गए अनुभव से पता चलता है कि योजना कार्यान्वयन और मूल्यांकन प्रक्रिया में नीति से प्रभावित होने वाले लोगों को शामिल करने से नीति अधिक स्वीकार्य हो जाएगी। हालाँकि, न्च् नीति में कुछ समस्याएँ आ रही हैं। वहाँ 100रू1 का बहुत ऊँचा विद्यार्थी–शिक्षक अनुपात था, पुस्तक अनुपात 1 पुस्तक से 6.7 विद्यार्थियों का था। यह स्पष्ट हो रहा था कि नीति सस्ती नहीं थी। सरकार जो राशि वहन कर सकती थी वह भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए बहुत कम थी। स्कूल छोड़ने की दर बहुत अधिक थीय नीति की वांछनीयता पहले से ही सवालों के घेरे में थी।

बाल श्रम से निपटने के लिए सभी हितधारकों द्वारा अलग–अलग तरीकों की आवश्यकता होती है। आईआरसी (2006) के अनुसार, सरकार शिक्षा के माध्यम से किशोर और बाल श्रम को कम करने के अवसरों (ORACLE) परियोजना में भाग ले रही है, USDOL द्वारा वित्त पोषित एक 4 साल की न्च् तीन मिलियन परियोजना और अंतर्राष्ट्रीय बचाव समिति और अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवकों के लिए इतालवी एसोसिएशन द्वारा कार्यान्वित की गई है। सेवा। कुछ परियोजना भारत में संक्रमणकालीन और गैर–औपचारिक शिक्षा और परिवार आधारित गरीबी उन्मूलन रणनीतियों के प्रावधान में संघर्ष–प्रभावित बच्चों के बीच बाल श्रम के सबसे खराब रूप के उन्मूलन और रोकथाम में योगदान देती है।

बजट सीमा से लेकर एचआईवी/एड्स महामारी जैसे कई कारकों के कारण कई देशों में शिक्षकों की अत्यधिक कमी के कारण ईएफए लक्ष्यों को प्राप्त करना समस्याग्रस्त हो गया है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षकों को उचित रूप से प्रशिक्षित और भुगतान किया जाना चाहिए, मीड (2005)।

निष्कर्ष

बाल नीति के सफल कार्यान्वयन के लिए सभी हितधारकों द्वारा नीति निर्माण प्रक्रिया में भाग लेने के प्रयासों की आवश्यकता होती है। सरकार, शैक्षिक प्रबंधकों और प्रशासकों, शिक्षकों और बड़े पैमाने पर समुदाय सभी को इस प्रक्रिया में शामिल होना चाहिए। गरीबी, जो मुख्य रूप से

बाल श्रम का कारण रही है, से पर्याप्त रूप से निपटा जाना चाहिए। यह रोजगार सृजन, समुदाय के लिए कम ब्याज वाले ऋण का प्रावधान और प्रत्येक जिले में तकनीकी संस्थान खोलकर किया जा सकता है, जो उत्पादन कौशल को प्रशिक्षित करता है जो स्व–रोजगार के लिए आवश्यक है।

निःशुल्क शिक्षा की शुरूआत बाल श्रम से निपटने का एक महत्वपूर्ण तरीका था, खासकर उप–सहारा अफ्रीकी क्षेत्रों में, जहां अधिकांश समुदाय अपने बच्चों के लिए स्कूल की फीस का भुगतान नहीं कर सकते थे। हालाँकि, नीति को अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए भ्रष्टाचार से कड़ा संघर्ष करना होगा। हालाँकि नीति को अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए भ्रष्टाचार से कड़ा संघर्ष करना होगा। मंत्रालय, स्थानीय सरकार और स्कूल प्रणाली से लेकर यह भ्रष्टाचार, सभी के लिए शिक्षा (ईएफए) के लक्ष्य को प्राप्त करने में बाधा रहा है।

खराब नेतृत्व, खराब कार्यक्रम प्रबंधन, ओवरलैपिंग अधिकार क्षेत्र, लक्ष्यों की खराब स्पष्टता और अपर्याप्त संसाधनों से उत्पन्न होने वाली अन्य समस्याओं को अलग से नहीं निपटाया जाना चाहिए। सरकार को कानून तोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, यूपीई कार्यक्रम को पर्याप्त रूप से वित्त पोषित करना चाहिए, यह सुनिश्चित करना चाहिए कि स्कूलों में कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है।

समुदाय को बच्चे और परिवार तथा समग्र समुदाय दोनों के लिए शिक्षा के महत्व के बारे में संवेदनशील बनाया जाना चाहिए।

सन्दर्भः

[1]. मजमीमार तंबूवाल (2012) राष्ट्रीय विकास पर स्ट्रीट भीख मांगने का प्रभाव ूंबंकमउपं. मकन।

[2]. माथियास, बी., (2014)। अंम्बरा राज्य में माध्यमिक विद्यालयों में बच्चों के शैक्षणिक प्रदर्शन पर बाल श्रम के प्रभावः अवका दक्षिण स्थानीय सरकार क्षेत्र में चयनित स्कूलों का एक अध्ययन। स्वास्थ्य और सामाजिक पूछताछ के अंतर्राष्ट्रीय जर्नल 2(28)26।

[3]. नवाउवा, एल।, (2018)। उच्च विद्यालयों में बाल श्रम और शैक्षणिक प्रदर्शन के निर्धारक https//www-smemantic cholar-org

[4]. ओके, के।, आयोडेल, के।, अलाडेनुसी, ओ।, और ओयिनलोय, सी। (2016)। माध्यमिक विद्यालय के छात्रों के अकादमिक आत्मविश्वास के भविष्यवक्ता के रूप में शैक्षणिक प्रेरणा, संतुष्टि और लचीलापन। आईओएसआर जर्नल ऑफ रिसर्च एंड मेथड इन एजुकेशन (आईओएसआर। जेआरएमई)

[5]. रैडफर, ए।, असगरजादेह, एसए, क्वेसाडा, एफ।, और फिलिप, आई।, (2018)। बाल श्रम की चुनौतियां और परिप्रेक्ष्य। औद्योगिक मनोरोग जर्नल, 27 (1):17–20।

[6]. उडो, जे। (2012)। अकादमिक प्रदर्शन पर स्ट्रीट हॉकिंग का प्रभावः www.iosrjournals.org संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल शिक्षा कोष, (2019)। शिक्षा–यूनिसेफ

[7]. वुल्फ, एम.एम., वुल्फ एमजे, फ्रॉली, टी।, टोरेस, ए।, और वुल्फ, एस। (2012)। उच्च शिक्षा में सहयोग के माध्यम से सीखने को बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करना। एप्लाइड एप्रोच्ड इकोनॉमिक्स एसोसिएशन वार्षिक सम्मेलन स्कैटल वाशिंगटन में एक केस स्टडी प्रस्तुति।

[8]. अकिंडेहिन, एफ. और अकिंडेहिन, एम. (2012) अकादमिक प्रदर्शन पर सोशल मीडिया पर बिताए गए समय के निहितार्थ।

[9]. एशिनोलोवो, ओ.आर. और एरोमोनलार्गा, ए.के. (2010)। व्यापारिक गतिविधियाँ और इसके पीड़ितों की शैक्षिक उपलब्धियों पर इसका प्रभाव। जर्नल ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस, 2,(4)

[10]. एकाटेरिना, पी।, डैनियल, एल।, ग्रेने, जी।, डैनियल, एच। (2017)। स्टूडेंट्स एंगेजमेंट, रिटेंशन और एकेडमिक अचीवमेंट बढ़ाने के लिए रामिफाइड मोबाइल ऐप का इस्तेमालः हायर एजुकेशन में इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी।

[11]. हेवन, पी. (2012): हू आईक्यू इज नॉट एवरीथिंग, इंटेलिजेंस, पर्सनैलिटी और स्कूल में एकेडमिक परफॉर्मेंस। पश्चिमी सिडनी विश्वविद्यालयय ऑस्ट्रेलिया।

[12]. जोस्ट, बी। (2012)। ऑनलाइन पाठ्यक्रमों में शैक्षणिक प्रदर्शन आयु, लिंग और जातीयताः सामुदायिक कॉलेज जर्नल ऑफ रिसर्च एंड प्रैक्टिस।